आमोखस व मिडिया की खबरों व प्रथम समाचार पत्र

RNI No. UPHIN/2012/47484

जननायक समाट

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों अलीगढ़ हाथरस ऐटा कासगंज बदायूं बुलंदशहर मथुरा आदि से प्रसारित व अलीगढ़ से प्रकाशित

बर्ष :13 अंक :520 पृष्ठ -4 दिनांक 08 जुलाई 2025 दिन मंगलवार

राजा आनंद सिंह के निधन पर सीएम योगी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं जताया दुख, जानें- क्या कहा?

पूर्व सांसद और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मनकापुर राजघराने के राजा आनंद सिंह का बीती रात लखनऊ में निधन हो गया. 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके बेटे कीर्ति वर्धन सिंह केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री हैं. उनके निधन पर यूपी की तमाम बड़ी सियासी हस्तियों ने दुख जताया और दिवंगत आत्मा की शांति का प्रार्थना की है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा आनंद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा–

मा. केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी के पूज्य पिता जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद श्री आनंद सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि

राजा आनंद सिंह अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे. सपा अध्यक्ष ने उनके निधन पर कहा, श्यूपी सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद गोंडा निवासी राजा आनंद सिंह जी का निधन, अत्यंत दुःखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं. भावभीनी श्रद्धांजलि

केशव मौर्य ने जताया निधन पर दुख

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शोक व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया अक. ाउंट एक्स पर लिखा– श्मा. केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी के पूज्य पिता जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद श्री आनंद सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. प्रभु श्रीराम जी दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकसंतृप्त परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति एवं संबल प्रदान करें.श्सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने लिखा– श्उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद, गोंडा निवासी राजा आनंद सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें.।

पीलीभीत में सिपाही के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शेयर किया आरोपियों का वीडियो

पीलीभीत के थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस से मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि फरार आरोपियों की तलाश कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है. ये पूरी घटना थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित ढका मोहल्ले की है.पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए आरोपियों का माफी मांगते हुए वीडियो पुलिस सेल से पोस्ट किया है जो अब जमकर वायरल हो रहा है. जमीन पर पड़े चारों आरोपी रहम की भीख मांगते हुए और अपनी गलती की माफी मांगते हुए साफ देखे जा सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में किस तरह से जनता की सुरक्षा करने वाले खाकी के सिपाही को भीड़ में लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी. दरअसल बीती रात पूरनपुर थाने में तैनात महावीर नाम का सिपाही अपने साथी वेरेंद्र सिंह नाम के पुलिस कर्मी के साथ गश्त कर रहे थे. उसी समय देर रात उनके हल्के में आने वाले ढका मोहल्ले में देर रात एक दुकान खुली थी. जिसको लेकर पुलिस कर्मियों ने अनाधिकृत समय से खुली दुकान बंद करने को कहा इतनी सी बात पर दुकानदार के परिजनों गाली गलौच करते हुए सिपाही पर ताबड़तोड़ हमला कर जूते चपल्लो से उसे पीटना शुरू कर दिया. पीडित सिपाही के साथ मौजूद सिपाही ये सब मूक दर्शक बना खड़ा देखता रह गया. किसी तरह पीडित सिपाही ने भाग कर अपनी जान बचाई. और घटना की जानक. ारी थाने में दी इसके बाद आरोपी दबंगों के खिलाफ पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी संगीन धाराओं में फिर दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर फरार आरोपी की तलाश कर कार्रवाई में जुटी है.पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि थाना पूरनपुर में पुलिस गश्त की जा रही थी,उसी दौरान सिपाही से मारपीट का मामला संज्ञान में आया है आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर फरार आरोपियों की तलाष कर करवाई की जा रही है.

ग्रेटर नोएडा के लाल ने किया देश का नाम रोशन, अमेरिका में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे वतन, हुआ जोरदार स्वागत

अमेरिका के बर्मिंघम शहर में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसमें स्वर्ण पदक जीतकर लौटे ग्रेटर नोएडा के लाल राजेश भाटी का शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया. उन्हें लेने के लिए भारी संख्या में परिजन, गांववाले और समर्थक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और ढोल–नगाड़ों के साथ विजेता का सम्मान किया गया है. उनके द्वारा हासिल इस उपलब्धि पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है और दूर–दराज से उन्हें खूब बधाई और प्यार मिल रहा है.जमालपुर गांव के निवासी राजेश भाटी ने इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय पुलिस दल का प्रतिनिधित्व करते हुए कुश्ती में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. उन्होंने फाइनल मुकाबले में अमेरिका के पहलवान जेम्स को हराकर देश का नाम रोशन किया. इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने न सिर्फ अपने गांव और राज्य का, बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया.राजेश भाटी वर्तमान में सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं. खेलों के प्रति उनकी रुचि बचपन से रही है, जो उन्हें अपने दादा, स्वर्गीय चरण सिंह पहलवान से वि. रासत में मिली. बता दें राजेश इससे पहले साल 2015 में अमेरिका के वर्जीनिया में हुए वर्ल्ड पुलिस गेम्स में दो स्वर्ण पदक जीत चुके हैं.इसके साथ ही, वे श्उत्तर प्रदेश केसरीश का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं. तमाम उपलब्धियां हासिल करने के बाद एक बार फिर राजेश ने अपने देश का परचम अमेरिका में लहरा दिया है. जिससे वह भी काफी खुश हैं. स्वागत के दौरान लोगों ने राजेश पर फूलों की बारिश की और ढोल–नगाड़ों के साथ पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर जश्न मनाया. इस मौके पर राजेश ने कहा यह जीत मेरे देश, मेरे गांव और मेरे परिवार को समर्पित है. उन्होंने कहा आने वाले समय में भी मैं देश के लिए और पदक लाने की कोशिश करूंगा.उनकी इस जीत से पूरे ग्रेटर नोएडा में खुशी की लहर है, और वे आज के युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं. परिवार, गांव और उनके दोस्त जमकर उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं, जिससे राजेश भी पूरी तरह गदगद दिख रहे हैं.

चार बच्चों का पिता 4 बच्चों की मां को लेकर हुआ फरार, पंचायत ने किया परिवार सहित बहिष्कार

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक चौंकाने वाली घटना में, चार बच्चों के पिता ने चार बच्चों की मां के साथ शादी करके गांव में तहलका मचा दिया. इसके बाद दर्जनों गांवों की पंचायत ने प्रेमी के खिलाफ सामा. जिक बहिष्कार और संबंध विच्छेद का ऐलान कर दिया. हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने कानून का हवाला देकर कोई कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया. झारखंड बॉर्डर के पास दो गांवों के बीच यह सनसनीखेज मामला सामने आया है. चार बच्चों का पिता और चार बच्चों की मां के बीच प्रेम संबंध बनने के बाद दोनों गांव से फरार हो गए. कुछ दिनों बाद, दोनों ने किसी मंदिर में शादी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो देखकर महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पड़ोसी गांव के युवक ने उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी को फुसलाकर भगा लिया. पुलिस ने लंबी खोजबीन के बाद दोनों को ढूंढ निकाला, लेकिन जब युगल ने थाने में आपसी सहमति से रहने की बात कही, तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया. इस घटना से नाराज दर्जनों गांवों के लोगों ने महाप. ंचायत बुलाई और ऐतिहासिक फैसला सुनाया, प्रेमी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, साथ ही उनसे सभी सामाजिक संबंध तोड़े जाते हैं. इस महापंचायत में ग्राम प्रधान सुरेंद्र पासवान, राकेश पासवान, मुन्ना पासवान, विनोद गौड़, दीपक गुप्ता, गोपीचंद पासवान, देव कुमार पासवान, राधेश्याम पासवान, कैलाश पासवान, कृपा शंकर पासवान, विजय पा. सवान और महेंद्र पासवान समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे. पुलिस ने इस मामले में कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. थाना प्रभारी ने कहा दृ चूंकि दोनों वयस्क हैं और अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते.अब सवाल यह है कि क्या पंचायत के सामा. जिक बहिष्कार के फैसले के बावजूद यह जोड़ा समाज में रह पाएगा? क्या पुलिस कभी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करेगी? ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

महोबा के सुगिरा गांव में 200 साल से कायम हिंदू मुस्लिम एकता

महोबा की कुलपहाड़ तहसील में बसा सुगिरा गांव मोहर्रम के अवसर पर हिंदू–मुस्लिम एकता की जीवंत मिसाल पेश करता है. यहां हर साल दसवीं मोहर्रम पर दो ताजिए निकाले जाते हैंकृ एक हिंदू समुदाय द्वारा और दूसरा मुस्लिम समुदाय द्वारा. यह 200 साल पुरानी परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि गंगा–जमुनी तहजीब और सामुदायिक सौ. हार्द का प्रेरणादायक उदाहरण भी है.गांव के बुजुर्गों के मुताबिक, इस परंपरा की नींव सुगिरा नरेश राव महिपत जूदेव ने रखी थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. अंग्रेजों द्वारा भूरागढ़ किले में उनकी फांसी के बाद, गांववासियों ने उनकी इस परंपरा को जीवित रखने का संकल्प लिया. तब से लेकर आज तक, हिंदू और मुस्लिम समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर मोहर्रम मनाते हैं. हिंदू समुदाय इमाम हसन और हुसैन की शहादत को उतनी ही श्रद्धा के साथ याद करता है, जितना मुस्लिम समुदाय.ग्रामीण देवेंद्र यादव बताते हैं कि हमारे गांव में हिंदू समुदाय पूरी श्रद्धा के साथ एक ताजिया तैयार करता है और जुलूस निक. ालता है. दूसरा ताजिया मुस्लिम समुदाय की ओर से निकलता है. यह परंपरा हमारी एकता और भाईचारे का प्रतीक है. वहीं मुस्लिम समुदाय के अकबर अली मंसूरी कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई इमाम हुसैन की कुर्बानी को दिल से समझते और सम्मान देते हैं. यह सिर्फ धर्म की बात नहीं, बल्कि इंसानियत और त्याग की भावना का सम्मान है. दोनों समुदाय न केवल मोहर्रम, बल्कि एक–दूसरे के सभी त्योहारों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेते हैं.सुगिरा गांव की यह परंपरा उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब देश के कई हिस्सों में धार्मिक भेदभाव और तनाव की खबरें सामने आती हैं. सुगिरा का मोहर्रम मातम का नहीं, बल्कि मजहबी मेल–मिलाप और सौहार्द का प्रतीक बन चुका है.

उत्तराखंड में सब्जियों पर पड़ी बारिश की मार, 1 महीने में दोगुना–तिगुना हुए दाम, बिगड़ा रसोई का बजट

उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानों तक मानसून की दस्तक के साथ सब्जियों के दामों में भी लगातार वृद्धि हो रही हैं। पिछले एक महीने में कई सब्जियों के दाम दोगुने से लेकर तीन गुने तक होने आम आदमी की रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है. वहीं व्यापारियों का कहना है आने वाले समय में सब्जी के दामों में और अधिक तेजी आ सकती है. उधम सिंह नगर जिले में 20 मई के बाद से सब्जियों के दामों में बढ़ोत्तरी होना शुरू हो गई थी. अब मानसून की दस्तक के साथ नदी किनारे स्थित सब्जी की खेती को नुकसान होने लगा है जिसके कारण सब्जी के रेटों में काफी तेजी के साथ इजाफा हो रहा हैं. 20 मई को करेला, तोरई, कद्दू 10 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में था. लेकिन, अब इनमें से कई सब्जियों के दाम दोगुने से लेकर तीन गुने तक हो गए हैं. सब्जियों के दामों में लगातार हो रही वृद्धि का असर आम आदमी की रसोई पर देखने को मिलने लगा है. कई सब्जियां रसोई से गायब होने लगी है क्योंकि सब्जियों की खरीदारी के लिए लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. सब्जी व्यापारी नेमचंद्र गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड में बरसात की दस्तक के साथ ही सब्जी की फसलों को काफी नुकसान होना शुरू हो गया है. जिसके कारण अब दामों में वृद्धि भी होने लगी है.

टमाटर	10रू.	40रू.लौकी	
15रू. .	30रू.भिंडी	20रू	
50रू बैंगन	25रू.	50रू.	
खीरा	15रू.	40रू करेला	
20रू.	50रू.कद्दू	20रू.	
30 रू.तोरई	20रू.	50रू	
परवल	30रू.	70रू.	

सब्जी के दाम बढने से कई लोगों कम मात्रा में सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं. ग्राहक अविनाश वर्मा ने बताया कि पिछले एक महीने में सब्जियों के रेटों काफी तेजी से वृद्धि हुई है. आलू और प्याज को छोड़ दिया जाएं, तो बाकी सभी सब्जियों के रेट बढ़ चुके हैं. सब्जियों के दामों में होने वाली वृद्धि का असर सीधे आम जनता की रसोई पर पड़ता है. इसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए.

यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी 356 सीटें प्रदेश में बढ़ेंगे विशेषज्ञ, राज्य सरकार ने जारी किए बजट

लखनऊ। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में परास्नातक (पीजी) की सीटों के बढ़ने का क्रम जारी है। राज्य के 13 स्वशासी मेडिकल कॉलेजों ने इस सत्र में पीजी सीटों के लिए नेशनल मेडिकल कम. ीशन(एनएमसी) में आवेदन किया है। पीजी सीटों के सापेक्ष मानक पूरे करने के लिए राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को बजट भी जारी किया है। अभी तक प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इस साल पीजी की करीब 356 सीटें बढ़ चुकी हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज कुमार द्वारा झांसी मेडिकल कॉलेज को विभिन्न विषयों की 17 पीजी और 50 एमबीबीएस सीटों के सापेक्ष करीब सवा सात करोड़ रूपए जारी किए हैं। इसी प्रकार कानपुर मेडिकल कॉलेज को 55 पीजी सीटों के लिए 19 करोड़ 75 लाख रूपए, प्रयागराज को सवा तीन करोड़, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज को 30 पीजी सीटों के लिए छह करोड़ 95 लाख, जालौन मेडिकल कॉलेज को पांच पीजी सीटों के लिए तीन करोड़ 59 लाख रूपए जारी किए हैं, इसी प्रकार आगरा मेडिकल कॉलेज में 72 एमबीबीएस सीटों के लिए आठ करोड़ 37 लाख रूपए जारी किए हैं। उक्त बजट के बाद कॉलेजों में उपकरण समेत अन्य संसाधन व बिल्डिंग आदि कार्य संपन्न होंगे। मालूम हो कि प्रदेश में केजीएमयू समेत 44 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 5250 सीटें हैं, मगर सभी में पीजी नहीं हैं, जिसकी वजह से एमबीबीएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीजी में दाखिला लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और एमबीबीएस अभ्यर्थियों की जरूरत को देखते हुए मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें शुरू करने के लिए संसाधन जुटाने के निर्देश दिए थे, उक्त क्रम में अयोध्या, बहराइच, बस्ती, देवरिया, फिरोजाबाद, जा. ंनपुर, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बदायूं, आजमगढ़, बांदा, जालौन, कन्नौज, कानपुर, झांसी, प्रयागराज के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मानक पूरे होने के बाद 356 पीजी सीटें बढ़ चुकी हैं।

अमेरिका से हो रहे इस समझौते के बीच राकेश टिकैत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी बड़ी मांग

भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले समझौते से कृषि और डेयरी क्षेत्र को बाहर रखा जाए, क्योंकि यह ग्रामीण भारत पर सीधा प्रहार होगा. इसके लागू होने से पहले से घाटे की खेती कर रहा देश का किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा.किसान नेता राकेश टिकैत ने पत्र के माध्यम से कहा कि, ष्अमे. रिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिनांक 01.04. 2025 को सभी देशों के परस्पर टैरिफ बढ़ाने की घोपणा की गई थी, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल था. अब इस घोषणा की समय अवधि दो दिन बाद दिनांक 09.07.2025 को पूर्ण होने वाली है और इस विषय को लेकर दोनों देशों के मध्य वार्ता का दौर अब अन्तिम चरण में पहुँच गया है.ष्कृषि और डेयरी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ राकेश टिकैत ने कहा, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि अमेरिका भारत पर लगातार कृषि और डेयरी क्षेत्र में बाजार खोलने के लिए दबाव बना रहा है. अगर यह सम्भव होता है तो करोड़ों किसानों और छोटे उत्पादकों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा. भारत का कृ षि और डेयरी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि यह हमारे ग्रामीण समाज का जीवन स्रोत है.किसान नेता कहा कि अमेरिका जैसी पूँजीवाद और बड़े कारपोरेट आधारित कृषि व्यवस्था के लिए भारतीय बाजारों को खोला गया तो देश का किसान बड़ी कारपोरेट कम्पनियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, साथ ही यह कदम आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य पर सीधा प्रहार है.

रिश्तेदारों की कहासुनी में जमकर मारपीट,दो पक्षों में चले लाठी डंडे, ईट चलाने से कई लोग घायल

हाथरस के मुरसान कोतवाली क्षेत्र के गांव गिलोंदपुर में एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में एक परिवार के रिश्तेदारों और कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ। इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने–सामने आ गए।विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी–डंडे और लात–घूंसे चलने लगे। वहां पर शोर गुल मच गया। महिलाएं भी इस झगड़े में कूद पड़ीं। जमकर धक्का मुक्की हुई। बीच–बचाव करने आए लोगों के साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने ईंटें भी हाथ में उठा ली। इससे वहां और ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई।कई लोगों का आई चोट इस हिंसक घटना में कई लोगों को चोट आई है। पूरे गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जानकारी कर रही है।

हाथरस में मौसम में बदलाव आया

हाथरस में आज सुबह से मौसम में बदलाव आया। आसमान में घने बादल छाए रहे। जिले के विभिन्न हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।बारिश के कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई। स्कूली बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंचे। सुबह लोगों की सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कुछ इलाकों में पहले से मौजूद जलभराव की स्थिति और बिगड़ गई।बारिश के चलते कई स्थानों पर विद्युत लाइनों में फॉल्ट आ गया। इससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। मौसम विभाग के अनुसार, कल जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था। वहीं आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बिजली कटौती से परेशान लोगों ने लगाया जाम वाहन चालकों को रोका, सब स्टेशन का भी घेराव, मौके से गायब हुए कर्मी

हाथरस में बिजली कटौती से नाराज काशीराम टाउनशिप के निवासियों ने जलेसर रोड पर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने विद्युत सब स्टेशन का घेराव भी किया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुईं और नारेबाजी की।लोगों के आक्रोश को देखते हुए विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारी मौके से गायब हो गए। प्रदर्शन के कारण सड़क पर यातायात बाधित हो गया। कुछ वाहन चालकों ने जब रास्ता निकालने की को. शिश की, तो प्रदर्शनकारियों से उनकी बहस हो गई।कोतवाली प्रभारी लोगों को समझा कर जाम खुलवाते हुए।कोतवाली प्रभारी लोगों को समझा कर जाम खुलवाते हुए।स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले तीन दिन से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा दिया है। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम..गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। सूचना मिलने पर कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और जाम खुलवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हो गया। इस दौरान करीब 1 घंटे बाद यातायात सुचारू हो सका।

आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र 111.5 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, किसानों को मिलेंगे उन्नत बीज

आगरा के सींगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। मोदी सरकार ने इस केंद्र के निर्माण के लिए 111.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की हैइस उपलब्धि के लिए किसान नेता मोहन सिंह चाहर का हाथरस के सादाबाद में किसानों ने भव्य स्वागत किया। विद्यादेवी कोल्डस्टोर में आयोजित कार्यक्रम में कोल्डस्टोर मालिक गौरीशंकर गौतम और पूर्व जिला अध्यक्ष किसान संघ अरुणेश वार्ष्णेय के नेतृत्व में किसानों ने उन्हें राधे कृष्ण की तस्वीर और पटका भेंट किया।उन्नतशील आलू बीज उपलब्ध होंगेमोहन सिंह चाहर ने बताया कि यह केंद्र अमेरिका के पेरू लीमा की शाखा के रूप में काम करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।अनुसंधान केंद्र से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। यहां से निर्यात योग्य प्रजातियों के उन्नतशील आलू बीज उपलब्ध होंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा और आलू का निर्यात भी होगा। निर्यात से किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।कार्यक्रम में श्यामवीर प्रधान, मुकेश दीक्षित, बंटी ठाकुर, अजय शर्मा, शिव सिंह, अजय सिंह, अनूप कुमार, मुकेश कुमार, मंजूर अहमद, राज मोहम्मद सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

सादाबाद को मिली नई अल्ट्रासाउंड स्वास्थ्य सुविधा एमडी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड केंद्र शुरू, आईटीआई छात्रों को मिले टैबलेट

सादाबाद के हाथरस रोड स्थित एमडी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड केंद्र की शुरुआत हो गई है। सांसद अनूप वाल्मीकि और भा. जपा जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी ने केंद्र का उद्घाटन किया।इस सुविधा से सादाबाद और आसपास के गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। अब उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए आगरा या अलीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों बचेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर गर्भवती महिलाएं भी यहां अल्ट्रासाउंड करा सकेंगी।कार्यक्रम में आ. ईटीआई के विद्यार्थियों को टैबलेट भी बांटे गए। नेताओं ने छात्रों को टैबलेट का सही उपयोग करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों नेताओं ने अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि वृक्षों की देखभाल बच्चों की तरह करनी चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होगा और ऑक्सीजन मिलेगी।अस्पताल के संचालक धर्मेंद्र गौतम ने पट्टिका और माला पहनाकर दोनों ने. ताओं का स्वागत किया।

पति को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला सादाबाद में 3 साल पहले हुई थी शादी, पुलिस से मांगी सुरक्षा

दिल्ली में रह रही सादाबाद की एक विवा. हिता ने अपने पति को छोड़कर ससुराल के ही एक युवक के साथ जाने का फैसला किया है। महिला की शादी तीन साल पहले सादाबाद के एक युवक से हुई थी।दिल्ली में रहते हुए महिला के ससुराल के ही एक युवक से प्रेम संबंध हो गए। आठ दिन पहले वह अपने प्रेमी के साथ चली गई। अब वह पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रही है।इस मामले का एक

शिव मंदिरों व कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली मांस मदिरा की दुकानों को बंद कराने की उठाई मांग

हाथरस।जनपद के कस्बा सादाबाद आदर्श महिला एवं बाल कल्याण संस्था की बैठक बीते दिन संस्था के जिला कार्यालय कूपा गली बरी वाला मोहल्ला में आहूत की गई थी जिसमें संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद थे।बैठक को संबोधित करते हुए संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा राणा ने कहा कि आने वाले दिनों में हिंदुओं के पवित्र महीना सावन माह की शुरुआत होने वाली है जिसके तहत कस्बा में शिव मंदिरों व कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली मांस मदिरा की दुकानों को बंद रखने हेतु एसडीएम संजय चौधरी को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया।इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा को जनपद में सकुशल संपन्न कराया जाए और कांवड़ शुरू होने से पहले मंदिरों की साफ–सफाई, बिजली,पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।जर्जर विद्युत खंभों को ठीक कराने और ट्रांसफार्मरों को जाली से ढकने के निर्देश दिए जाए साथ ही जनपद के सभी सीएचसी को सक्रिय करने के साथ ही कांवड़ मार्ग पर प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त एंबुलेंस व्यवस्था की जाए।वहीं बड़े मंदिरों में बैरिकेडिंग और पार्किंग की व्यवस्था की जाए।महिला पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा राणा ने कस्बा की सादाबाद तहसील पहुंच कर एसडीएम संजय चौधरी को ज्ञापन दिया। जिस पर एसडीएम ने संस्था की महिला पदाधिकारियों के साथ उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा राणा को आश्वासन दिया कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान रखते हुए उचित इंतजाम किया जाएगा।इस मौके पर आदर्श महिला एवं बाल कल्याण संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा राणा और संस्थापक मनीष कौशिक के अलावा राष्ट्रीय उप सचिव धीरज दूबे,प्रदेश महामंत्री राजकुमार सनातनी,प्रदेश अध्यक्ष नेहा गुप्ता,राखी देवी,पूनम देवी,ऊषा देवी, कोमल,श्यामू देवी,पूनम वर्मा,दिनेश बघेल, जानू चौधरी और अनिल चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

इस संबंध में कोई लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज नहीं है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ने अपने पति पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है।महिला का कहना है कि वह अब अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। उसे डर है कि उसका पति उसके साथ कोई दुर्घटना कर सकता है।सीओ सादाबाद हिमांशु माथुर ने बताया कि यह मामला दिल्ली क्षेत्र का है। इस पर दिल्ली पुलिस ही कार्रवाई करेगी। कोतवाली सादाबाद में

जनहित सुझावों पर हुई चर्चा–शहर में विकास और जनहित समस्याओं के निस्तारण के प्रस्ताव पर सहमति की लगाई मोहर

महापौरध्नगर आयुक्त का वादा–नगर निगम संपत्तियो का बनेगा डिजिटल रजिस्टर–3 साल से अधिक समय से तैनात नगर निगम कार्मिको का बदलेगा पटलअलीगढ़ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक महापौर प्रशांत सिंघल की अध्यक्षता में उप सभापति दिनेश जादौन कार्यकारिणी सदस्य अनिल सेंगर, योगेश सिंघल, असलम नूर, आसिफ,करन माहौर, निरंजन सिंह, मो. हफीज अब्बासी, मो.शाकिर, रीनू सैनी, मो. गुलजार, मुशर्रफ हुसैन महजर की उप. स्थिति में कल्याण सिंह हैबिटेट के सभागार में सम्पन्न हुई। कार्यकारिणी बैठक परम्परागत राष्ट्रीय गीत से शुरू हुई तत्पश्चात सचिव सचिवालयध्सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने कार्यकारणी सदस्यों के जनहित सुझावों व प्रस्तावो को पढ़ कर सुनाया। कार्यकारणी बैठक में महापौर और नगर आयुक्त की सहमति से सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा हुई।पार्षदों को मिलेंगे सवालो के जवाबकार्यकारिणी सदस्यों ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर समय से नही पहुँचने के बारे में महापौर व नगर आयुक्त को बताया। नगर आयुक्त ने पार्षदों को आश्वस्त किया भविष्य में बैठक से 2 दिन पहले सभी सवालों के जवाब के पत्र प्राप्त कराये जाएगा। वर्कशॉप से संबंधित उप सभापति के सवाल का समय से जवाब नही देने पर प्रभारी अधिकारी वर्कशॉप को नगर आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस देने व भविष्य में पार्षदों के जनहित सवालो के जवाब को भेजने के लिए अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव को नामित किया।संपत्तियों का डिजिटल रजिस्टर व बदले जायेगे कार्मिककार्यकारिणी सदस्यों ने नगर निगम की समस्त संपत्तियों का डिजिटल रजिस्टर बनवाये जाने का प्रस्ताव व नगर निगम के विभिन्न पटलों पर 3 साल से अधिक तैनात लिपिकोंध्कर्मचारियों का स्थानांतरण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। जिस पर महापौर व सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया। बैठक में नगर आयुक्त ने सदस्यों को आश्वस्त किया अगले 1 हफ्ते में 3 साल से अधिक समय से एक पटल देख रहे कर्मचारियों को बदला जाएगा।'नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी बैठक में बताया किनगर आयुक्त ने जी0आई0एस0 सर्वे के सम्बंध में सदन को अवगत कराया कि नागरिक को जी0आई0एस0 सर्वे के उपरान्त कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जायेगा। जी0आई0एस0 सर्वे से संपत्ति कर निर्धारण और संपत्ति कर रोपण की विषम स्थिति का समाधान हो सकेगा, इस सर्वे से नगर निगम के पास संपत्ति करदाता का नाम मोबाइल नंबर ईमेल आ. ईडी, व्हाट्सएप, संपत्ति कर एसेसमेंट सहित अन्य महत्वपूर्ण ब्यौरा नगर निगम में संकलित हो सकेगा, नगर निगम आ. सानी से प्रॉपर्टी मालिकों की पहचान कर सकेगा, टैक्स जमा करने का मैसेज व्हाट्सएपध्एसएमएस के माध्यम से एक क्लिक में जा सकेगा। टैक्स चोरी को रोक सकेगे, क्यूआर कोड के उपयोग से, टैक्स प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी और लोगों को टैक्स भरने में आसानी होगी। जीआईएस सर्वे से नगर निगम प्रत्येक प्रॉपर्टी का एक विस्तृत डेटाबेस बना सकेगा और सर्व उपरांत भवनों पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा क्यूआर कोड को स्कैन करके, लोग आसानी से अपने घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करके, नगर निगम के अधिकारी संपत्ति के मालिक और अन्य विवरणों को जान सकेंगे।वर्कशॉप में पुराने वाहनों की मरम्मत आदि पर अव्यय को रो. कने के लिए नगर निगम वर्कशॉप व जलकल विभाग के कण्डम वाहनों व स्पेयर पार्ट्स की नीलामी जल्द की जा रही है।शहर की डेयरियों को नगर निगम सीमा से बाहर ले जाने के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से निरंतर संवाद किया जा रहा है इसके लिए जल्द शहर के चार स्थानों का चयन किया जाएगापाइपलाइन डालने के कारण जल निगम द्वारा सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के दृष्टिगत नगर आयुक्त ने बताया जल निगम द्वारा पिछले 1 साल में हैंडोवर किये गए पानी की टंकी, ट्यूबवेल, पाइप लाइन, सड़क आदि का ऑडिट समिति द्वारा कराया जाएगा।शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार के लिए नगर आयुक्त ने बताया शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार के लिए आने वाले दिनों में वार्ड वाइज लाइटों के रख रखाव संचालन और मेंटेनेंस का जिम्मा थर्ड पार्टी को देने का निर्णय लिया गया है साथ ही साथ लाइट विभाग में कोई भी टेंडर भविष्य में नोएडा और चंडीगढ़ की तर्ज पर ऑटोमेशन के साथ होगा।भविष्य में नाला सफाई को दृष्टिगत रखते हुए पूरे साल का टेंडर इसी जुलाईध्अगस्त से ही उठाये जाने की प्रकिया की जा रही है इस प्रक्रिया से नाला सफाई में सुधार आएगा व पूरे साल नाले साफ हो सकेगे।स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार के लिए आठ अवर अभियंता यांत्रिक जैम पोर्टल से आप. र्ति ली जा रही है।जल निकासी और पेयजल आपूर्ति को प्रभावी बनाने के लिए जलकल विभाग में मात्र एक सहायक अभियंता और अवर अभियंता होने के कारण समस्याओं की निदान में समय लगता है जिसको दृष्टि कर सकते हुए जैम पोर्टल से 15 अवर अभियंता आउटसा. र्स पर जेम पोर्टल से आपूर्ति ली जा रही है आपूर्ति उपरांत जल निकासी और पेयजल आपूर्ति प्रभावी बन सकेगी।नगर आयुक्त का वादानगर आयुक्त ने कार्यकारिणी बैठक में नगर निगम संपत्ति विभाग की कार्यशैली को सुधारने के लिए संपत्ति विभाग का प्रभार बदलने, संपत्ति प्रभारी को कारण बताओ नोटिस देने, नगर निगम के सभी पटल बाबुओं को बदलने व नगर निगम संपत्तियों का डिजिटल रजिस्टर बनवाये जाने के बारे में महापौर व सदस्यों को अवगत कराया और कहा अगले 7 से 10 दिनों में उक्त व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा।महापौरध्नगर आयुक्त का सदस्यों ने जताया आभारकार्यकारिणी सदस्यों ने निर्माण कार्यो में गति आने के लिए महापौर व नगर आयुक्त का आभार व्यक्त किया। महापौर व नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से कहा निर्माण कार्यो में लाप. रवाही व गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नही किया जाएगा आने वाले समय में निर्माण कार्यो गुणवत्ता के मानकों को प्रभावी बनाने के लिए आईआईटी रुड़कीध्कानपुर से सैम्पल को चौक कराया जाएगा।कार्यकारणी में सदस्यध्उपसभापति ने अलीगढ़ में विकास कार्यो व जनहित समस्याओं जैसे नाला सफाई, जीआईएस सर्वे, जल भराव, लाइट व्यवस्था, सीवर , निर्माण कार्य, पेयजलापूर्ति, हाउस टैक्स बिल वितरण जैसे बिन्दुओ पर चर्चा हुई।ये प्रस्ताव हुए पास बैठक में प्रस्ताव संख्या 1अचल तालाब पर निर्मित 32 दुकानों को नियमानुसार उच्चतम बोली के आधार पर नियमानुसार निर्धारित प्रीमियम एवं किराए पर उठाये जाने हेतु, प्रस्ताव संख्या 2 सुरेंद्र नगर पानी की टंकी परिसर मे मा०विधायक कोल अलीगढ के आग्रह पर पुलिस चौकी निर्माण हेतु नगर निगम के स्वामित्व की 200 व0मी0 भूमि वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक को निशुल्क हस्तान्तरण हेतु एवं प्रस्ताव संख्या 3 मा0 महापौर के आदेश दिनांक 03ध06ध्2025 द्वारा ई रिक्शा लाइसेंस फीस मे 10: छूट 30 जून 2025 तक बढ़ाये जाने के संबंध में कुल 3 प्रस्तावों पर कार्यकारणी सदस्यों ने सहमति की मोहर लगाई।. महापौर का बयानमहापौर प्रशांत सिंघल ने कहा आने वाले समय में अलीगढ़ नगर निगम विकास की नई परिभाषा लिखेगा वर्तमान बोर्ड और पार्षदों के सहयोग से जनकल्याणकारी योजनाओं और शासन के अनुदान से अलीगढ़ में विकास कार्य तेजी से होंगे कार्यकारिणी बैठक में सफाई व्यवस्था स्ट्रीट लाइट पेयजलापूर्ति और जल निकासी को प्रभावी बनाने के लिए जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनके जमीनी रूप लेते ही शहर में बदलाव देखने को मिलेगा।ये रहे मौज. ूदबैठक में मंचासीन महापौर प्रशांत सिंघल नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव सचिव सं. चवालय वीर सिंह उपसभापति दिनेश जादौन कार्यकारिणी सदस्य अनिल सेंगर,योगेश सिंघल,असलम नूर,आसिफ,करन माहौर,निरंजन सिंह मो. हफीज अब्बासी,मो.शाकिर,रीनू सैनी,मो. गुलजार,मुशर्रफ हुसैन महजर उप नगर आयुक्त अमित कुमार नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश कुमार मुख्य अभियंता सुरेश चंद महाप्रबंधक जल पीके सिंह सहायक लेखाधिकारी भारत दुबे कर निर्धारण अधिकारी आरपी सिंह पशु कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय सक्सेना महामंत्री मानवेन्द्र सिंह बघेल स्टोनो देश दीपक सतीश शर्मा मीडिया सहायक एहसान रब विजय गुप्ता तरुण पाठक राजीव कुमार डॉ तरुण शर्मा मुकुल शर्मा आदि मौजूद थे।

श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत एसएसपी ने आयोजकों के साथ की बैठक

अलीगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में 11 जुलाई से आरम्भ हो रहे श्रावण मास के प्रथम सोमवार 14 जुलाई, द्वितीय सोमवार एवं शिवरात्रि 21 जुलाई, हरियाली तीज 27 जुलाई, तृतीय सोमवार 28 जुलाई, चतुर्थ सोमवार 04 अगस्त एवं रक्षाबंधन 09 अगस्त महत्वपूर्ण पर्वों के दृष्टिगत जिले में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था एवं कानून–शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, एसपी सिटी मृगांक पाठक समेत समस्त एसडीएम, सीओ एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।एसएसपी संजीव सुमन ने नगर निगम एवं सभी नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रमुख बाजारों, मंदिरों एवं भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर विशेष साफ–सफाई सु. निश्चित कराई जाए। जल भराव की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के लिए भी निर्देशित दिए गए। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक तैयारियां करने और फाल्ट होने की स्थिति में तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती एवं ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष यातायात योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि पर्वों के दौरान यातायात बाधित न हो। सभी एसडीएम व

सीओ को अपने–अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें कराने और स्थानीय लोगों के सहयोग से साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए गए एसएसपी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि पर्वों के दौरान नागरिकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। डीजे की ऊँचाई मानक के अनुरूप रखे जाने के निर्देश दिये गए। इस दौरान उन्होंने सभी एसडीएम एवं सीओ से संयुक्त रूप से बारी–बारी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि वह नियमित रूप से संयुक्त भ्रमण करें, हर छोटी–बड़ी घटना की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। बैठक में खेरेश्वर धाम, अचलेश्वर, पथवारी मन्दिर, शिव मंदिर अनूप शहर रोड, भूमिया बाबा मंदिर, शिव मंदिर बि. जौली से आए आयोजकों से भी उनकी समस्याओं को सुन निराकरण करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। शिविर स्थापना मार्ग से हट कर किनारे बाई तरफ की जाए ताकि आवागमन में परेशानी न हो। खाद्य सुरक्षा एवं अग्निशमन अधिकारियों को हर प्रकार से तैयार रहने और समय से पूर्व शिविर एवं खाद्यान्न की जाँच करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी–अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीम भावना के साथ कार्य करें। एसपी ट्रैफिक ने कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए चार प्रमुख मार्गों पर साइनेज, प्रकाश व्यवस्था एवं बैरियर का कार्य समय से पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि कोई नई परंपरा के साथ ही निर्धारित रूट व्यवस्था से इतर कांवड यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जाए।

बच्चों को विटामिन–ए की खुराक पिलाने के लिए 9 जुलाई से विशेष अभियान

अलीगढ़ जिले में 9 जुलाई से 9 अगस्त तक 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन–ए की खुराक पिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियों के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 नीरज त्यागी की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। सीएमओ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, सीडीपीओ, चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को अभियान को पूरी गंभीरता से संचालित करने और लक्षित 5 लाख से अधिक बच्चों तक शत–प्रतिशत खुराक पहुंचाने के निद. श दिए।सीएमओ ने कहा कि विटामिन–ए की कमी से बच्चों में अंधापन और कुपोषण की समस्या हो सकती है, इसे रोकने के लिए यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और टीकाकरण सत्र स्थलों पर बच्चों को विटामिन–ए की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विटाामिनए की खुराक दो चरणों में 06 माह के अन्तराल पर दी जाती है, जिससे बच्चों की रोध प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। उन्होंने यह भी बताया कि एएनएम द्वारा बच्चों को विटामिन–ए की खुराक केंद्र पर ही पिलाई जाएगी।

विश्व जूनोसिस दिवस पर जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए कलक्ट्रेट में जागरूकता बैठक आयोजित

अलीगढ़ विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर कलैक्ट्रेट सभागार में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 नीरज त्यागी ने की। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं संबंधित कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।सीएमओ डॉ0 नीरज त्यागी ने अधिकारियों से अपील की कि वे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आमजन को जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूक करें ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही इन रोगों की पहचान कर उपचार किया जा सके और महामारी की स्थिति को टाला जा सके। बैठक में रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक रणनीति अपनाने का भी संकल्प लिया गया।बैठक में मुख्य रूप से जूनोटिक रोगों की महत्ता पर चर्चा करते हुए डॉ0 शोएब ने बताया कि जूनोटिक रोग वे संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, जैसे रेबीज, ब्रूसेलो. सिस, बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स। इन रोगों का समय पर निदान और रोकथाम न होने पर ये मानव जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं।उन्होंने जूनोटिक रोगों के संक्रमण के प्रमुख तरीकों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि संक्रमित पशु के सीधे संपर्क में आने, दूषित भोजन या पानी का सेवन करने, पशुजनित उत्पादों का अनुचित उपयोग एवं मच्छर या टिक जैसे वाहकों के माध्यम से संक्रमण शामिल है। उन्होंने बताया कि पशुपालन में साफसफाई रखना, समय पर पशुओं का टीकाकरण कराना, संक्रमित पशु के संपर्क से बचना एवं संक्रमित पशु या उनके उत्पादों को उपयोग में लाने से पूर्व आवश्यक सतर्कता बरतना, संक्रमण की रोकथाम में अत्यंत सहायक सिद्ध होता हैबैठक में जूनोटिक रोगों के कारणों, उनके लक्षणों एवं निवारण के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डॉ0 शोएब ने बताया कि पशु एवं मानव स्वास्थ्य के बीच समन्वय को मजबूत कर ही जूनोटिक रोगों के प्रसार को रोका जा सकता है।

जिला कृषि अधिकारी ने किसान भाईयों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति किया जागरूक

अलीगढ़ जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने किसान भाईयों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करते हुए बताया है कि उर्वरकों के असंत. ुलित प्रयोग से मृदा एवं पर्यावरण की क्षति होती है साथ ही कृषि निवेशों से लागत में भी वृद्वि होती है जबकि उपज में कोई सक. ारात्मक परिणाम नहीं आते है।उन्होंने बताया कि वर्तमान में पीएम प्रणाम योजना के अन्तर्गत यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं इनके पोषक तत्वों को अन्य उर्वरक के माध्यम से पूर्ति किया जाना है, जिससे कि मृदा एवं पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहें। कृषक भाई अपनी जोत बही के अनुसार ही उर्वरक क्रय करें अनावश्यक भण्डारण न करें व फसलों में संस्तुत उर्वरकों का ही प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि किसान भाई उर्वरक खरीदने के लिए आधार कार्ड साथ ले जायें और विक्रेता से कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें।. उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया है कि वह कृषकों को उर्वरक उनकी कृषि, जोत, फसल के अनुसार एवं उनके आधार कार्ड व आधार पंजीकरण संख्या के आधार पर दें और उर्वरक बिक्री की कैश मेमो अनिवार्य रूप से दिया जाये। विक्रय प्रतिष्ठान पर स्टाक एवं रेट का अंकन प्रतिदिन करें। प्रतिष्ठान पर उपलब्ध उर्वरक के स्टाक एवं रेट बोर्ड प्रतिदिन डि. स्प्ले किया जाये। नाइट्रोजन उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का उपयोग करें। नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग 02 अवस्था में 35 व 50 दिन के अन्तराल पर करें।इफको कम्पनी प्रति. निधि द्वारा अवगत कराया गया कि नैनो यूरिया की एक बोतल एक बैग यूरिया की जगह ले सकता है। नैनो यूरिया का प्रयोग पत्तियों पर किया जाता है। नैनो यूरिया आसानी से रन्धों एवं छिद्रों के माध्यम से पौधे में प्रवेश कर जाता है और पौधों की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जड़ शोधन व बीज शोधन के लिए नैनो डीएपी उर्वरक का भी प्रयोग करें साथ ही 50 दिन के अन्तराल पर वानस्पतिक अवस्था में टॉप ड्रेसिंग भी करें। उर्वरक की उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को उर्वरकों का प्रयोग सही समय, सही जगह, सही तरीके एवं संतुलित मात्रा में करना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग सामान्यतः सुबह एवं शाम के समय में करना चाहिए व ऑधी तुफान एवं वर्षा के समय उर्वरक का प्रयोग करने से बचना चाहिए।डीएओ श्री चौधरी ने कृषक भाइयों एवं उर्वरक विक्रेताओं से अपील की है कि वह संस्तुत मात्रा के अनुसार उर्वकों का क्रयविक्रय करें, जिससे फसल व मृदा पर रसायन के नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय अथवा प्रचलित उत्पाद के साथ गैर प्रचलित उत्पाद टैग किये जाये तो उक्त दशा में संम्बन्धित की शिकायत जिला कृषि अधिकारी कार्यालय अलीगढ़ के नियंत्रण कक्ष मोबाइल नं0– 8954918916 एवं 9504997660 पर की जा सकती है।

गंगेरवाल जैन सभा की कार्यकरिणी बैठक एक पेड़ मां के नाम अभियान से जैन समाज को जुड़ने की अपील

अलीगढ़।गंगेरवाल जैन सभा अलीगढ़ कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में समाज के व्यक्तियों को मेडिकल संबन्धित सहायता देने के क्रम में कैंसर की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत आने वाली पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देकर जायेंगे इसी के क्रम में वृक्षारोपण करने का भी निर्णय लिया साथ ही धार्मिक यात्राओं के आयोजन पर भी विचार विमर्श किया गया।इसके अलावा समाज में अपनी सेवाओं को निष्ठा के साथ पूर्ण कर सेवानिवृत व्यक्तियों एवं विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को संस्था द्वारा आगामी पर्युषण पर्व पर सम्मा. नित करने का भी निर्णय लिया गया।बैठक के समापन पर अध्यक्ष राजीव जैन ने सभी का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्री नीरज जैन द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही एवं संस्था द्वारा किए जा रहे समाजिक एवं धार्मिक कार्यों का विवरण दिया।वहीं उप मंत्री मयंक जैन ने समाज को एकजुट होकर समाज हित के कार्य करने के लिए अपील की।बैठक में कार्यकारिणी में ने सदस्य विशाल जैन एवं दिलीप जैन के सम्मिलित होने पर स्वागत एवं सम्मान किया गया।बैठक में हरिकांत जैन,प्रमेंद्र जैन,राकेश जैन,हेमंत जैन, विनय जैन,पवन जैन,पंकज जैन,यतीश जैन,दीपक जैन,प्रमोद जैन,कुलदीप जैन, प्रदीप जैन,प्रशांत जैन,मनोज जैन,राजा जैन,सौरभ जैन और कुणाल जैन उपस्थित रहे।

अलीगढ़ के पड़ाव दुबे पर स्थित लगभग सौ साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया

अलीगढ़ के पड़ाव दुबे पर स्थित लगभग सौ साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। इतना ही नहीं इस अवसर पर यहां मंदिर परिसर से ठाकुर जी के डोले ने बैंड बाजों के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया और इस यात्रा में श्रद्धालुओं ने नाचते गाते हुए अपनी सहभागिता निभाई और इसके बाद विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देवी देवताओं के विग्रहों को पुनःस्थापित कराया। खास बात ये है कि इस मंदिर की तीन पीढ़ियों से सेवा कर रहे रजत वार्ष्णेय बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण यहां पर वर्ष 1902 में उनके दादा जी ने कराया था और तब से लेकर अब तक ये प्राचीन मंदिर यहां के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इतना ही नहीं इस मंदिर की हालत काफी जर्जर हो गई थी जिसके चलते यहां पर पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ इसका जीर्णोद्धार कराया गया है।महानगर के पड़ाव दुबे स्थित प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के बाद पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम श्रद्धालु मुख्य रूप से उपस्थित रहे जबकि यहां पर ललित वार्ष्णेय ने सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया।

अकराबाद–छर्रा के बाद गंगीरी को तहसील बनाने की उठी मांग, बाजार बंद कर निकाली रैली

अलीगढ़ जनपद में पांच तहसीलों के बाद अकराबाद को तहसील बनाने की बात सामने आई। उसके बाद छर्रा को तहसील बनाने की मांग उठी। अब गंगीरी को भी तहसील बनाने की मांग उठने लगी है। गंगीरी क्षेत्र के लोगों को साथ मिलकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने गंगीरी को तहसील बनाने की मांग करते हुए रैली निकाली। 7 जुलाई को पूरा बाजार बंद कराकर नायब तहसीलदार मंयक गोयल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में गंगीरी को तहसील बनाने की मांग के साथ कस्बा के मुख्य मार्ग पर जलभराव से निजात दिलाने की मांग की। गांव धन. सिंहपुर पर काली नदी पर पुल बनाने की अपील भी की। ग्रामीणों ने बताया है कि मुख्य मार्ग के पास ही पोखर थी। इसमें

नालियों के जरिए पानी जाता था, लेकिन अब उसे पोखर को मिट्टी डालकर पाट दिया है।अब घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर ही भर जाता है। गांव धनसिंहपुर पर काली नदी पर एक पुलिया छर्रा विधायक की पहल से बनी थी। पिछले साल बारिश में वह पुलिस ढह गई। अब लोग यहां मजबूत पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनुज वार्ष्णेय, मोती बजाज, प्रशात वार्ष्णेय, डॉ. विष्णु कुमार कुशवाहा, हरिओम शर्मा आदि मौजूद रहे।

हाथरस पुलिस लाइन में तैनात 39 वर्षीय फॉलोअर रामकुमार का साइलेंट हार्ट अटैक से निधन

हाथरस पुलिस लाइन में तैनात 39 वर्षीय फॉलोअर रामकुमार का साइलेंट हार्ट अटैक से निधन हो गया। अलीगढ़ के क्वार्सी के रहने वाले रामकुमार हाथरस पुलिस लाइन के क्वार्टर में रहते थे। सा. मवार को दोपहर 1 बजे के करीब रामकुमार की तबीयत अचानक बिगड़ी। वह क्वार्टर में बेहोश होकर गिर पड़े।स. हकर्मी उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गए। सहकर्मियों का कहना है कि अस्पताल में रामकुमार को 20 मिनट तक कोई इलाज नहीं मिला। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से सहकर्मियों की बहस हुई। चिकित्सकों ने रामकुमार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव

का पोस्टमार्टम कराया।सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे और शव को अपने साथ ले गए। मृतक के दो बच्चे हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर सूर्य प्रकाश का कहना है कि रामकुमार को मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति का उपचार किया जाता है।

बिहार में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए

बिहार में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या राज्य की कानून–व्यवस्था के लिए चुनौती है। जिस तरह से राजधानी पटना के एक पॉश इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे सरकार के क्राइम कंट्रोल के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है और इसका चुनावी फायदा लेने की को. शिशें भी होंगी।बिहार में अपराध हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है। करीब दो दशक की सत्ता में श्रक् अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में यही गिनाती है कि उसने राज्य को लालू के जंगल राज से बाहर निकाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ठश्रच के नेता किसी भी मौके पर लालू–राबड़ी के कार्यकाल में हुए अपराधों की याद दिलाने से नहीं चूकते। लेकिन, गोपाल खेमका हत्याकांड हर सरकारी दावे पर एक सवाल की तरह है। डीएम ऑफिस के पास वारदात बताती है कि अपराधियों में पुलिस–प्रशासन का डर नहीं है, और यह भी कि संगठित अपराध फिर से सिर उठा रहा है इजरायल–हमास युद्धरू वाइट हाउस में सीजफायर पर होगी डील, ट्रंप के साथ निर्णायक बैठक, क्या नेतन्याहू के हाथ में हैं सारे पत्ते?सिंघम से कम नहीं हरियाणा की ये महिला प्ैे, देर रात क्लबों, शराब ठेकों और नाकों पर मारा छापा, मचा हड़कंपपाकिस्तान ने दिया अपने दोस्त चीन को धोखा! इस बड़ी डील से किया इनकार, चाल या अफवाह? जानें पूरा मामला

अपराधरू समस्या है कि बिहार से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तीन दिन पहले ही सीवान में तीन लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। वहीं, पिछले महीने 10 साल की रेप विक्टिम की मौत ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था। आरोप है कि बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिला। ऐसी हर वारदात नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है।आंकड़ों का सहारारू 2005 से अभी तक, त्श्रक के बिना या उसके साथ, नीतीश जब भी सत्ता तक पहुंचे, तो क्राइम कंट्रोल के वादे के साथ। बिहार के लोगों को हमेशा यह अहसास कराया गया कि नीतीश ही अपराध पर लगाम लगा सकते हैं। सरकार अपने समर्थन में नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो का डेटा दिखाती है, जिसके हिसाब से अपराध के मामले में बिहार से भी ऊपर कई राज्य हैं। श्रक् ने इस साल मई आखिर में छब्त्ठ के हवाले से बताया था कि देश मे अपराध की दर 422.2 प्रति लाख है, जबकि बिहार में 277.1 प्रति लाख।विपक्ष के लिए मौकारू हालांकि आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं बताते। हर अपराध जनता का भरोसा तोड़ता है। आज के समय की तस्वीर ऐसी बन रही है, जहां बिहार में अपराधी फिर से बेखौफ हो रहे हैं। इससे विपक्ष को भी पलटवार का मौका मिला है। त्श्रक और कांग्रेस नेता श्जंगलराज के आरोपोंश को उठाकर अभी के हालात पर सरकार को घेर रहे हैं। यह मुद्दा आगामी चुनाव तक नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आंकड़ों से अलग, उनकी सरकार को जमीन पर यह साबित करना होगा कि उनके शासन में बिहार ज्यादा सुरक्षित है।

नए आपराधिक कानूनों की स्वीकार्यता, भारत की न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और नागरिक–अनुकूल बना रहे

सुनील कुमार गुप्ता और अक्षिता गुप्ता। एक जुलाई, 2024 को भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को तीन आधुनिक विधियों–भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) से बदल दिया। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिक–केंद्रित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी–सम्मिलित आ. पराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण करना था। लागू होने के पहले दो महीनों में ही इन नए प्रविधानों के तहत 5.56 लाख से अधिक एफआइआर दर्ज हुईं, जो इनकी सक्रिय स्वीकार्यता को दर्शाती हैं। इसके साथ ही 5.6 लाख से अधिक पुलिस, अभियोजन और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जो प्रशासन की तैयारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।भारतीय न्याय संहिता ने संगठित अपराध, आतंकवाद और भीड़ हत्या जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जिससे यह वर्तमान समय की आपराधिक प्रकृति के अनुरूप बन गई है। इसमें कुछ अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है, जो दंडात्मक न्याय से सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक न्याय की ओर एक संवे. दनशील कदम है। हालांकि कई प्रविधान अब भी आइपीसी से मिलते–जुलते हैं, लेकिन यह निरंतरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने का एक व्यावहारिक तरीका माना जा रहा है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने प्रक्रिया संबंधी कानून में क्रांतिक. ारी बदलाव लाया है। अब नागरिक जीरो एफआइआर और ई–एफआइआर दर्ज कर सकते हैं और केस फाइलें और चार्जशीट डिजिटल रूप में तैयार की जा रही हैं। जांच अधिकारियों को स्मार्टफोन और टै. बलेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे घटनास्थल से तुरंत साक्ष्य एकत्र कर सकें और अपलोड कर सकें। दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुलिस स्टेशनों में वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं जिससे रिमांड और गवाही की कार्यवाहियां दूरस्थ रूप से की जा सकें। उत्तर प्रदेश इस दिशा में अग्रणी राज्यों में से है। राज्य के सभी 75 जिलों में मोबाइल फारेंसिक वैन तैनात की गई हैं । इसके अलावा 60,000 नए भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ताकि वे नवीन विधिक व्यवस्था में प्रशिक्षित हो सकें।बीएनएसएस के अंतर्गत मोबाइल फारेंसिक साइंस यूनिट्स का विस्तार एक प्रमुख सुधार है। इसके साथ ही फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जा रहा है, ताकि वे साइबर अपराध और डीएनए परीक्षण जैसे जटिल मामलों की जांच कर सकें। हालांकि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 32 पूर्ण रूप से कार्यशील एफएसएल थीं, लेकिन हालिया निवेश से स्थिति में सुधार की दिशा स्पष्ट ह।भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल युग की मांगों के अनुरूप साक्ष्य कानून को अद्यतन करता है। अब ईमेल, मेटा डाटा, सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस डाटा और यहां तक कि ब्लाकचेन रिकार्ड को भी कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हैश वैल्यू और डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिए गए हैं। अदालतें अब ई–गवाही और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ साक्ष्य स्व. ीकार कर सकती हैं। विशेष रूप से 22 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा विकसित ई–साक्ष्य एप को अपनाया है, जिससे डिजिटल साक्ष्य को संग्रहित और प्रस्तुत करना सरल हो गया है। ये परिवर्तन ई–कोर्ट्स परियोजना की बुनियाद पर निर्मित हुए हैं, जिसके तहत 18,000 से अधिक अदालतों का डिजिटलीकरण किया गया है और आनलाइन फाइलिंग एवं वीडियो सुनवाई की व्यवस्था पहले से अस्तित्व में है।हालांकि सुधारों की दिशा में ठोस प्रगति हुई है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की असमानता बाधा बन रही हैं। फारेंसिक प्रयोगशालाएं सीमित हैं और अदालतों तथा पुलिस स्टेशनों में कर्मच. ारियों की कमी भी गंभीर विषय है। एनस. ीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2022 के बीच साइबर अपराधों में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो उच्च तकनीकी अपराधों से निपटने के लिए संसाधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दर्शाता है। इन सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ नीति–निर्माण उपाय आवश्यक हैं।सामुदायिक सेवा को एक संस्थागत दंड व्यवस्था के रूप में लागू किया जाना चाहिए, जिसके लिए न्यायिक प्रशिक्षण और दिशानिर्देश तय किए जाएं। बीएनएसएस के अंतर्गत गवाह संरक्षण नियमों को राज्य स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें पहचान छिपाने, स्थानांतरण और वीडियो गवाही की सुरक्षित व्यवस्था हो। प्रत्येक जिले में फारेंसिक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल और स्थायी, दोनों प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही एक राष्ट्रीय डिजिटल अनुपालन डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, जो एफआ. इआर, जांच की प्रगति और रिमांड की प्रक्रिया पर निगरानी रखे। अंततः विधिक साक्षरता अभियान चलाकर नागरिकों को नए कानूनों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।नए आपराधिक कानून एक सक. ारात्मक और सुविचारित बदलाव के प्रतीक हैं। पहले वर्ष में एक मजबूत आधार स्थापित हो चुका है। अब आवश्यकता है इसे और मजबूती से आगे बढ़ाने की। यदि यह यात्रा प्रशिक्षण, निवेश और नीति समर्थन से सशक्त की जाए, तो भारत की न्याय प्रणाली वास्तव में अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक–अनुकूल बन सकती है।

सरकार ने पाकिस्तान की हॉकी टीम और निशानेबाजों को भारत आने की अनुमति दे दी

सरकार ने पाकिस्तान की हॉकी टीम और निशानेबाजों को भारत आने की अनुमति दे दी है। पहलगाम जैसी आतंकी घटना का सामना करने के बावजूद भारत ने खेल भावना को बनाए रख परिपक्वता का सबूत दिया है।जिम्मेदारी भरा कदमरू भारत को हॉकी के एशिया कप और थ्प्भ् जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। इसके अलावा शूटिंग में प्ैैथ् जूनियर विश्व कप भी होना है। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए यह असमंजस बना हुआ था कि पाकिस्तान इन इवेंट्स में हिस्सा ले पाएगा या नहीं, लेकिन भारत ने जिम्मेदारी भरा परिचय दिया।खिलाड़ियों को सजा क्योंरू सरकार का यह फैसला ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के अंतर को सामने ला देता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का निशाना आम लोग बनते हैं, जबकि पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाते वक्त भी भारत ने यही कहा कि उसकी लड़ाई केवल आतंकियों से है, आम लोगों से नहीं। सरकार का मौजूदा फैसला भी इसी भावना से जुड़ा है। पाकिस्तानी इस्टैब्लिशमेंट के किए की सजा उसके खिलाड़ियों को देना सही नहीं होगा।रा. जनीति और खेल अलगरू भारत का कदम इंटरनैशनल हॉकी फेडरेशन और इंटरनैशनल ओलिंपिक कमिटी की नीतियों के अनुरूप है, जो खेल में निष्पक्षता और सहभागिता पर जोर देते हैं। खेल को रा. जनीति से नहीं मिलाया जा सकता। वैसे भी मेजबान होने के नाते भारत पर जिम्मेदारी ज्यादा है। उसे इन इवेंट्स में सभी प्रतिभागी देशों को समान मौके उपलब्ध कराने चाहिए और उसने यही किया।नियमों का सम्मानरू प्व्ब् और थ्प्भ् जैसी संस्थाओं के नियम बेहद कड़े हैं। पाकिस्तान को अनुमति नहीं देने पर खुद भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। ईरान ने अपने खिलाड़ियों को इस्राइल का सामना करने से मना किया और इसके चलते 2021 में इंटरनैशनल जूडो फेडरेशन ने उस पर बैन लगा दिया था। खुद पाकिस्तान ने जब 2019 में प्रो लीग हॉकी के पहले तीन मैचों से नाम वापस लिया, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था ने उसे पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया था। भारत ने नियमों का सम्मान किया है।भारत की उदारतारू खेल लोगों को जोड़ने का माध्यम बन सकता है। अतीत में हमने ष्चवतजे क्पचसवउंबल का कमाल देखा है, जिसकी वजह से बातचीत का रास्ता खुला। सरक. ारों के स्तर पर न सही, आम लोगों के स्तर पर संबंध सुधारने की हर पहल का स्वागत होना चाहिए।

मराठी भाषा के हित के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हाथ मिला लेने और मंच साझा करने पर हैरानी नहीं। रा. जनीति में यह सब होता रहता है। 20 साल बाद साथ आए ये दोनों नेता आगे चलकर फिर अलग हो जाएं तो अचरज नहीं। जो भी हो, हिंदी थोपने की फर्जी आड़ लेना और मराठी अस्मिता का हवाला देना निकृष्ट भाषाई राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। इसे ठाकरे बंधुओं ने यह कहकर साबित भी कर दिया कि हम दोनों मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करेंगे।वास्तव में यही मूल उद्देश्य है और इसी कारण हिंदी विरोध की कुछ वैसी ही समाज और देश विरोधी राजनीति की जा रही है, जैसी तमिलनाडु और कर्नाटक में देखने को मिलती रहती है। यदि ठाकरे बंधु और उनके समर्थक यह सोच रहे हैं कि हिंदी का हौवा खड़ाकर वे महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को भड़काने और राजनीतिक लाभ हासिल करने में समर्थ हो जाएंगे तो यह संभव नहीं।आमतौर पर लोग समझदार होते हैं और ऐसी घटिया राजनीति को अच्छे से समझते हैं। यह भी एक यथार्थ है कि कम से कम राजनीति में एक और एक ग्यारह नहीं होते। इसके तमाम उदाहरण अतीत में देखने को भी मिल चुके हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हिंदी विरोध की रा. जनीति उस महाराष्ट्र में की जा रही है, जहां हिंदी समर्थक नेता, साहित्यकार, गीत–संगीत के दिग्गजों की गिनती करना कठिन है। मुंबई तो हिंदी फिल्म उद्योग का घर है। हिंदी सिनेमा ने महाराष्ट्र के लाखों मराठी भाषी लोगों को काम, दाम और नाम दिया है। वे इसे स्वीकार भी करते हैं। क्या अब ठाकरे बंधु मुंबई से हिंदी फिल्म उद्योग बाहर करने की मांग करेंगे?तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भाषाई कट्टरपंथी कुछ भी कहें, देश की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत और प्रतिष्ठित है। यह भी एक सच है कि इस देश की कोई संपर्क भाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही है। अंग्रेजी यह काम नहीं कर सकती। उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का पोषण तो भारत की भाषाओं से ही हो सकता है और इस पोषण की आवश्यकता भी है।

सरकारी बंगले पर रार, सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ रहा पत्र

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को धन्यवाद कि उसने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की ओर से सरकारी बंगला न खाली करने पर केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि उनसे बंगला खाली कराया जाए। यह अभूतपूर्व है। दिल्ली अथवा देश के अन्य हिस्सों में सरकारी बंगलों में किसी को भी तय अवधि से ज्यादा रहने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है और अतीत में होता भी रहा है।यह ठीक है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने आठ माह बाद भी सरकारी बंगला खाली न कर पाने के कुछ कारण गिनाए हैं और इन कारणों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो है ही कि उन्हें नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वे अपने फैसलों और फैसलों से इतर संबोधनों के जरिये नैतिक आचरण पर बल देते रहे हैं।सरकारी बंगला विवाद से उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंच. ेगा। यह सही है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी बंगले में रहने के लिए तय किराया दे रहे हैं, लेकिन यह किराया कुल मिलाकर मामूली ही होता है और जिस इलाके में वे रह रहे हैं वह तो अति विशिष्ट क्षेत्र है।यह पहली बार नहीं है जब सरकारी बंगले को लेकर कोई विवाद उठा हो। इस तरह के विवाद पहले भी उठते रहे हैं। से सांसदों, पूर्व मंत्रियों की गिनती करना कठिन है जिन्होंने सांसद अथवा मंत्री न रहने के बाद सरकारी बंगला छोड़ने में आनाकानी की। कुछ नेताओं से तो जबरन बंगला खाली कराना पड़ा।यह भी एक तथ्य है कि कुछ नेता एवं पूर्व अधिकारी अथवा कथित विशिष्ट व्यक्ति सरकार की कृपा से लंबे समय तक सरकारी बंगलों में काबिज रहे। कुछ लोगों की ओर से यह भी कोशिश की गई कि उनके नेता की स्मृति संजोने के नाम पर उन्हें अथवा उनके स्वजनों को सरकारी बंगला सदैव के लिए आवंटित कर दिया जाए।दुर्भाग्य से ऐसे कुछ नेता अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए। ऐसा इसीलिए होता रहा, क्योंकि सरकारी बंगलों में किसे रहना चाहिए और किसे नहीं, इसके लिए जो नियम–कानून बने हुए हैं वे कुल मिलाकर कागजी ही अधिक हैं। इन नियमों पर सही तरीके से पालन मुश्किल से ही होता है। दिल्ली में केंद्र सरकार के बंगलों में अपात्र लोगों के रहने के किस्से तो चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन राज्यों के ऐसे किस्से दबे–छिपे ही अधिक रहते हैं।सच तो यह है कि कई राज्यों की राजधानियों में न जाने कितने अपात्र लोग सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। सरकारी बंगले राष्ट्र की संपत्ति हैं। किसी भी सरकार को इन्हें किसी को मनमाने तरीके से आवंटित करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में सरकारों को आदेश–निर्देश दिए हैं, लेकिन उन पर पालन शायद ही हो रहा होगा।